[Shri Kalyan Roy]

increased the price of the manganese ore by Rs. 20 per tonne, which has been opposed by the Janata Party itself, because it is in the private sector. He has increased the price of iron-ore by Rs. 4 per tonne, and he has admitted that this meant Rs. 3 crores per year for the MMTC which will be pocketed by four big companies. So, any amount of rise can be given to the manganese mine-owners who do not pay anything to the workers, any amount of price rise can be given to the mica mine-owners or the iron-ore mine-owners, but it would be denied to the public sector.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I think, you will take long. So, the House adjourns till 2-00 o'clock, and you will continue.

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri U. K. Lakshmana Gowda)** in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE —contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Mandal is not here?

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): What is the business before the House?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The business before the House is, Papers to be Laid on the Table.

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar): What is the business? Who is the Minister?

SHRI SHRI KANT VERMA (Madhya Pradesh): How can the House sit without any business?

Interim Reports of Shah Commission

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

(1) A copy each of the first and Second Interim Reports, dated March 13 and April 27, 1978, respectively, of the Commission of Inquiry headed by Justice J. C. Shah, enquiring into misuse of authority, excesses and malpractices committed during the Emergency together with a copy of the Memorandum of action taken on the Interim Reports.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for not laying simultaneously Hindi versions of the interim Reports and the Memorandum of action taken on the Interim Reports.

[Placed in Library. *See* No. LT-78 for (i) and (ii)].

SHRI RAMANAND YADAV: This is a bogus report. *(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Order, please. The Leader of the Opposition Mr. Kamlapati Tripathi is going to say a few words on that. He has been permitted to speak.

विपक्ष के नेता श्री कमलापति त्रिपाठी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं। मेरी समझ में इस रिपोर्ट का उपयुक्त स्थान सदन का पटल नही बल्कि रद्दी की टोकरी है। इस रिपोर्ट की बहुत सी बातें समाचार पत्रो में प्रकाशित हो चुकी हैं। सेक्रेटरीज़ की कमेटी की सिफारिशों का सारांश भी समाचार-पत्रों में छप चुका है। उन्ही से यह पता चल गया कि इस रिपोर्ट मे क्या है? यह रिपोर्ट एक ऐसे कमीशन ने तैयार की है मान्यवर, जो जनता पार्टी की सरकार की प्रतिशोध भावना का प्रतीक है; जनता पार्टी की सरकार ने बदला लेने की भावना से ओतप्रोत होकर जो षड्यंत्र रचा है उसका परिणाम यह कमीशन है। देश

की जनता ने इस सड़े हुए कमीशन को तिरस्कृत कर दिया है। यह रिपोर्ट पोलिटिकली मोटिवेटेड है। मान्यवर, यह रिपोर्ट एकतरफा है, वन-साइडेड है, अ बन्च आफ लाइज़ और झूठी है और बेबुनियाद बातों से भरी हुई है।. . .

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Order, order, please.

श्री कमलापति त्रिपाठी : यह रिपोर्ट द्वेषपूर्ण भी है मान्यवर। दुनिया में पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की जो जानकारी है उसके यह विरुद्ध है क्योंकि ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट में पार्लियामेन्ट के अधिकार और उसके निर्णय करने की क्षमता को चुनौती देने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूं कि सदन की पटल से इस रिपोर्ट को हटा कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए।

SHRI SHRIKANT VERMA: Sir,...

SHRI ANANT PRASAD SHARMA (Bihar): We want to say something on this...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Tripathi has already made a statement on that. Please sit down.

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है जैसा इस रिपोर्ट में है। शाह कमीशन को कोई अधिकार नहीं है। शाह के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। देश के पूंजीवादियों का शाह प्रशंसक * * * * है। उसको कोई अधिकार नहीं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के ऊपर रिपोर्ट दे। * *

* * * * शाह जिसके ऊपर 190 मेम्बर्स आफ पार्लियामेन्ट ने पत्र दिया था, * * * * *

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. If you go on like this, how can we conduct the proceedings?

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: But they also cannot go on like this. We have to react to it.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी,. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): What is it that you wanted to say, Mr. Bhandari?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार एक कमीशन नियुक्त हुआ था। यह स्वाभाविक है कि उसकी रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी जाए। यह अब सदन की सम्पत्ति है और सदन के प्रत्येक सदस्य को उस रिपोर्ट के बारे में अपने विचार प्रगट करने की खुली छूट है। माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति जब कमीशन नियुक्त हुआ था उस समय भी उठाई थी और इसलिए इस समय अपवाद लगाने या आपत्तियां उठाने की बात नयी बात नहीं है। यह सदन की परिपाटी रही है और यह सदन का अधिकार है कि जो भी कमीशन सदन की इच्छा के अनुसार नियुक्त होता है. .

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह गलत बात है. . (*Interruptions*)...It is a wrong statement.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : यह बात सही नहीं है। . .

(*Interruptions*)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह कमीशन बनाया हुआ है सरकार का।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आपको इस सदन के अंदर, एक मोशन के द्वारा कुछ भी कहने का अधिकार है। यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इस कमीशन . . .

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : क्या है जस्टिस शाह, कौन है ? जनता का विरोध करने वाला,**

(*Interruptions*)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : वह भी आप से ज्यादा इस भारत का एक प्रतिष्ठित नागरिक है।

कई माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी आपसे ज्यादा है।:

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के 190 मेम्बरों ने. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. Let us hear him.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री कमल नाथ झा (बिहार) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा है--शायद गुस्से में कहा हो, और मैं समझता हूं कि यह पार्लियामेंट पर और पार्लियामेंट के मेम्बरों पर एक एस्पर्सन है (*Interruptions*) आप एक इंडिपेंडेंट मेम्बर की आवाज भी नहीं सुनना चाहते। मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं। तो मैं कह रहा था कि अभी माननीय सदस्य ने यह कहा है और यह जबरदस्त एस्पर्सन है इस सदन के सदस्यों पर कि वह आप लोगों से ज्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित नागरिक हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन और सदन के सदस्यों से अधिक सम्मानित किसी को कहने का अधिकार किसी सदस्य को नहीं है क्योंकि यह संसद् भारत के नागरिकों की सर्वोच्च और सबसे गरिमा सपन्न संस्था है। इसलिए उनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए और इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Let us hear him. Please sit down.

श्री कमल नाथ झा ऐसा करके वह मिटीगेट करते हैं, सदन की गरिमा को।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. I do not know what he has said. Let us look into the records. Mr. Bhandari, did you say anything like that?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी मेरा यह निवेदन है कि . . (*Interruptions*)

श्रीमती सरोज खापडे (महाराष्ट्र) : हमसे अधिक प्रतिष्ठित नागरिक जिनको हमारे माननीय सदस्य ने अभी कहा है, मैं पूछना चाहती हूं कि यदि वह इतने ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं तो आज की जनता सरकार में जो मंत्री है उन्होंने ही कुछ दिन पहले इन्हीं जस्टिस शाह को भ्रष्टाचारी कहा था और आप कहते हैं कि वह हमसे भी अधिक प्रतिष्ठित नागरिक हैं। इस सदन में ऐसी बात कहना आपको कहां तक शोभा देता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभाध्यक्ष जी (*Interruptions*)

SHRI SHRIKANT VERMA: Please listen to me for one minute. This Commission was appointed to go into, and examine, the excesses of emergency. But it went beyond its terms of reference. It challenged even the imposition of emergency which was ratified by both the Houses of Parliament. So, this Commission has lost its credibility and laying the report of the Commission here is an insult to this House and I protest against it. I say that this should not go into the records. Otherwise, such things will happen and that will reduce the House to a public forum.

श्री देवराज पाटिल (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर बहुत सिंपल है। सम्माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा कि सदन की इच्छा से शाह कमीशन की नियुक्ति हुई। ऐसा कह कर इस सदन को और भारत की जनता को वह गुमराह कर रहे हैं। सदन ने डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली, ऐसा नहीं चाहा, न कोई रेजोल्यूशन पास किया और न कोई इच्छा प्रकट की। तो यह कहना कि सदन की इच्छा से शाह कमीशन की नियुक्ति हुई यह कहां तक ठीक है।

श्री रामानन्द यादव . मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है. . .

श्रीमती सरोज खापडे : उनको तो जार्ज फर्नेन्डीज ने कहा था कि यह * * * है। खुद उनके मिनिस्टर ने उनके बारे में यह कहा था। (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. Let him speak.

श्री रामानन्द यादव . उपसभाध्यक्ष जी, शाह कमीशन की नियुक्ति जिस परिवेश में हुई थी उसको सारा हिन्दुस्तान और यह सदन जानता है। शाह कमीशन की नियुक्ति राजनैतिक उद्देश्य से की गई। वह राजनैतिक उद्देश्य क्या था, यह हम और आप जानते हैं। इस पार्लियामेन्ट के चुनाव के बाद और कांग्रेस पार्टी की हार के बाद इस देश में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए जो लोग जनता पार्टी के थे और सत्ता में आये उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया और वह प्रयत्न यह था कि कांग्रेस पार्टी के . . . (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is all right. You cannot go on making a speech. (*Interruptions*). Please listen to me, Mr. Kalp Nath and

*Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Kureel. If you go on making long statements, it will be of no use. It can be discussed when the Report comes up for discussion in the House. There does not seem to be any point of order in whatever you say. So, Mr. Yadav, please finish saying what you have to say.

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि शाह कमीशन का यह मध्यकालीन रिपोर्ट है, पूर्ण रिपोर्ट नही है, अभी रिपोर्ट और आने वाली है। ऐसी स्थिति मे सदन के सामने यह रिपोर्ट पेश हुई। हम इस पर बहस करेंगे, जो भी बहस होगी वह अधूरी होगी। मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि क्या किसी कमीशन आफ एन्क्वायरी को मध्यकालीन रिपोर्ट पर हम बहस कर सकते है और जो बहस करेंगे, वह अधूरी नही होगी और हम किसी निर्णय पर नही पहुंच सकेंगे।

SHRI PIARE LALL KUREEL *URF* PIARE LALL TALIB (Uttar Pradesh): Sir, just one word. The imposition of the emergency was not the act of an individual, but it was the act of Parliament. It was ratified by the Cabinet and it was also ratified by Parliament and it had then become an Act of Parliament. Now, Parliament is the supreme body. Sovereignty lies in Parliament. Can any Commission challenge the sovereignty of our Parliament? Let me explain the whole thing. You see, it was an act of Parliament and no Commission can go into it. Excesses are inevitable. Firstly, you have to see whether the emergency was rightly imposed. It was imposed by Parliament. Emergency or no emergency, excesses are inevitable because that is due to the character of the police. When one guilty person was arrested, two persons who were not guilty were also arrested. So, excesses are inevitable No individual can be punished for excesses resulting from an act of Parliament.

SHRI PILOO MODY (Gujarat): Punishment is also inevitable.

SHRI PIARE LALL KUREEL *URF* PIARE LALL TALIB: But the appointment of this Commission is absolutely illegal. (*Interruptions*). You cannot appoint any Commission to challenge the sovereignty of Parliament. Then, throw away the concept of sovereignty of Parliament to dogs and make the Executive the sovereign body, but at present nobody can challenge the right of Parliament. This is in a way to undermine the sovereignty of Parliament. You cannot appoint any Commission to go into the charges of excesses.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is all right.

SHRI PIARE LALL KUREEL *URF* PIARE LALL TALIB: It is a colossal waste of public money. (*Interruptions*). Sir, it is a colossal waste of public money, I tell you. There is an ordinary way of dealing with such cases of corruption and other charges. Our Indian Penal Code is very exhaustive. A person can be convicted for sedition and also for treason. In the ordinary way, Sir, FIRs could have been lodged against any individuals and the cases ought to have been sent to the lower courts and there the witnesses would have appeared and cross examined and after the courts found that there was some substance in the charges against persons guilty of something, the courts could have sent the cases to the higher court for trial. The lower court has the right to send the case to a higher court for trial. But this sort of character assassination and this sort of vilification is not good and it is not democratic.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): All right. You have made your point. Yes, Mr. Kalp Nath Rai. Don't take much time.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, शाह कमीशन की कार्यवाही को शुरू किया इस सरकार ने और रोज रेडियो, अखबार में लगातार देश की महान् नेता इन्दिरा गांधी की करेक्टर की हत्या की। (*Interruption*) ऐसा शाह कमीशन के काम से किया गया। शाह कमीशन (*Interruption*) . . उपसभाध्यक्ष महोदय, शाह

कमीशन की जब जांच चल रही थी तो दक्षिण भारत मे इनकी करारी पराजय हुई। तब भी इन्होंने रेडियो और अखबार से इंदिरा गाधी की चरित्र हत्या करने के लिए सारे तरीके अपनाये। किन्तु जनता ने शाह कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी मे फेंक दिया (*Interruptions*)

आजमगढ़ का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव में जनता सरकार पूरी तरह हारी है। शाह आयोग की रिपोर्ट के आने पर भी ये बुरी तरह हारे हैं। इसमें बेहया लोग हैं। मैं मांग करता हू कि इस पालियामेंट को भग कराओ, लोक सभा को भग कराओ और फिर नये चुनाव कराओ। * * * ये देश के दुश्मन है।... (*Interruptions*)

आप जानते हैं कि संजय गांधी जेल मे है। अब उसको फंसाने के लिए एक जीप-काड हुआ है।

* * * । देश की हुकूमत आज इनके हाथ में आ गई है। मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के सम्मान के साथ खिलवाड करने की कोशिश आपने की तो इस मुल्क मे गृह-युद्ध होगा। ... (*Interruptions*) सारे देश में युद्ध होगा। इसलिए मैं चाहता हू कि मिड-टर्म पोल कराओ, मध्यावधि चुनाव कराओ। ... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Nothing will go on record... (*Interruptions*)

(*Several hon. Members continued speaking*)

श्री जगबीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, पाइंट आफ आर्डर है। जो भाषा इन्होंने प्रयोग की है वह अन-पार्लियामेंट्री है ... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down... (*Interruptions*)

श्रीमती सरोज खापडे : श्रीमन्, ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): This shall not go on record. It is not possible... (*Interruptions*) If everybody starts talking, we cannot go like that. Nothing has been recorded whether it was said from this side of the House or from the other side. (*Interruptions*) Will you kindly sit down? So many people asked for permission to say a few words. I have permitted. Mr. Bhandari was saying something. Then the points of orders came. Let us give a chance to one or two people. Then let us hear what the Leader of the House wants to say. After that we can proceed with the other business. Mr. Kulkarni.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, in the first instance, I want to know whether the report has been placed on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It has been placed.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: My second submission is that we have to discuss this report in a cool and objective manner. I can understand the feelings of my friends on the right and naturally so because the ex-Prime Minister was a respected leader of this country. Shah Commission was appointed. Its report is there. I would only request my friends on the right that blaming Mr. Shah or somebody else is not going to take us anywhere politically. The time has come when the people are again disbelieving the political system which this country has and of which we are proud. The credibility of that political system is in doubt at present. I would request everybody here that we should also uphold the democracy and the democratic pattern or our society in which the political system and its institutions carry much weight. Sir, I do not want to express any opinion about Mr. Shah. But I, as a representative of my party, would request you to allow a discussion on the Shah Commission Report because some of my friends, if I heard them

***Expunged as ordered the Chair.

correctly, called him corrupt. Mr. Kureel said that he was corrupt. The Shah Commission report relates to emergency and certain aspects of it. Now, Mr. Shah is not the godfather or a god-sent man. Sir, we are also equally responsible people. Let us assess what Mr. Shah has said. It is for the Government to take a decision. I do not know whether they will take a decision and bring it before the Parliament for taking a final decision. On behalf of my party, I would request that the Shah Commission report should be discussed in this session and if it is not possible, early in the next session. We should be given an opportunity for an objective discussion on the Shah Commission Report. As I said, the political system and the credibility of this system has come in doubt. The respect for judiciary has also come in doubt. It is not the fault of only this party. It is also the fault of the other party which has not given proper respect to the courts. Both the parties find it necessary to fight. But the Judges are there to give a decision on whatever evidence they receive. I would request all the political parties that respect for judiciary has to be maintained. It has not only to be maintained but it has to be increased in this country. There only lies the salvation of democracy. My last point is this. I would say in a lighter vein that the All India Radio should find more time for us. Many of us have spoken and our names should be there.

SHRI GIAN CHAND TOTU (Himachal Pradesh): Sir, in all humility, I would like to say that the Deputy Leader of the Janata Party has just now said two things, which are complete lies. The first thing that he said is that the Commission has been appointed with the consent of this House, and the second thing, which he said, is that Justice Shah is more respectable than Members of Parliament. Sir, this is not only unparliamentary but it is also undignified.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: I did not say this.

SHRI GIAN CHAND TOTU: Sir, he should be asked to apologise to this House and he should be asked to withdraw these remarks. If he refuses to apologise, I would request you, Sir, to delete that sentences from the proceedings, namely, that Justice Shah is more respectable that Members of Parliament.

SHRI PILOO MODY: In a democracy everybody is entitled to have his view. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I am not allowing you. I am only trying to help you, but every time somebody gets up.

श्री देवराज पाटील · श्रीमन्, मैं यह पाइन्ट रेज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने सदन मे जो कुछ कहा है, सदन के नियमों के अनुसार उसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। . . . *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You were also given a chance.

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat): Sir, he wants a specific ruling from you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I was trying to give a chance to Mr. Bhandari who had spoken for some time. Then, in between, he stopped him. You allow him. Afterwards we will see.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी · उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं इस देश के किसी भी नागरिक की भी इज्जत करता हूं और यह कदापि स्वीकार करने के लिए तैयार नही हूं कि भारत के किसी भी नागरिक की प्रतिष्ठा इस सदन के माननीय सदस्यों से कम है और मैं इसी चीज पर कायम हूं, जब तक कि आप कोई विपरीत निर्णय इस संबंध में नही देते है. . *(Interruptions)*

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्रीमन्, इन्होंने "प्रतिष्ठा ज्यादा है" कहा है . (*Interruptions*)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि . . (*Interruptions*)

SHRI PILOO MODY: But it is a matter of opinion.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी उपसभाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आप जो निर्णय देंगे, वह मुझे स्वीकार्य होगा। मैं उस तरफ के माननीय सदस्यों द्वारा कही जा रही बात को सही नहीं मानता हूं। . . . (*Interruptions*) . . . कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अधीन एक रिपोर्ट सदन के सामने आई है। . . . (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Let us hear him.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, he has clearly stated that he sticks to what he has said. Now, the hon. Member on this side has already raised a point of order. He want to know what your opinion is.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I cannot give any opinion. I will have to look into the records first. He says that he has not mentioned what you have said. We must see the record.

SHRI PILOO MODY: Mr. Vice-Chairman, Sir, everybody in this House is entitled to an opinion, except the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Of course that is what has happened. We have been witnessing that.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, शाह कमीशन की इंटेरिम रिपोर्ट सदन के सामने है। यह कहना कि इंटेरिम रिपोर्ट को सदन के सामने रखने से कोई लाभ नहीं होगा, उचित नहीं है। पहले भी अनेक बार इस सदन में इंटेरिम रिपोर्ट रखी गई है और सरकार की जो उस पर प्रतिक्रिया रही है वह भी सदन के सामने आई है। अब सदन उस पर किस स्टेज पर बहस करना उचित समझता है तो यह सदन की इच्छा पर है।

SHRI A. R. ANTULAY (Maharashtra). Sir, I rise on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Let him finish.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, अगर सदन इंटेरिम रिपोर्ट पर बहस करना आवश्यक नहीं समझता है तो फाइनल रिपोर्ट पर बहस कर सकता है। सदन के पटल पर इंटेरिम रिपोर्ट रखने मात्र से वह नहीं होता है कि उस पर चर्चा होगी। मैं समझता हूं कि इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। इतना जरूर है कि अब यह रिपोर्ट सदन की सम्पत्ति बन गया है। सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के साथ-साथ सदन के सामने रखी है। अब यह सदन की इच्छा पर होगा कि वह इस रिपोर्ट पर कब बहस करे इस समय कोई नई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। हर बार ऐसी रिपोर्टों के संबंध में जो नार्मल प्रेक्टिस रही है वही प्रेक्टिस इस रिपोर्ट के बारे में भी अपनाई गई है। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

SHRI A. R. ANTULAY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise on a point of order. In this debate, my hon. friend, Mr. Bhandari, did mention, as the hon. Member, Mr. Kamalnath Jha, raised the point of order, within the hearing of the entire House—there is no question of checking up of the record—that Mr. Justice Shah is more honourable than the Members of this House.

SHRI PILOO MODY: So what?

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: You may not understand. At least try to understand.

SHRI A. R. ANTULAY: Mr. Kamalnath Jha raised a point of order; another point of order was raised by Mr. Deorao Patil. That was with regard to another matter totally unrelated, whether the Shah Commission was or was not appointed with the consent of the House and Mr. Bhandari made a statement that the Shah Commission was appointed with the consent of the House. Now, these are the two statements which in my humble submission involve (a) matter of privilege and (b) matter of order of the business, and, therefore, I would request the Chair to kindly give the

rung on this. Both these statements have been made, have been uttered in the presence of the entire House; all of us have heard it and I feel the Chairman will give his ruling which is very essential, before we proceed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): So far as these particular references which you have made, are concerned, it will take some time to know from the proceedings. I would look into the proceedings.

Now Mr. Sharma wanted to say something and after that, I will ask the Leader of the House to speak.

SHRI SHYAM LAL YADAV: Sir, I wanted to say something. शाह कमीशन की इस रिपोर्ट का जो आधार है वह कपोल कल्पित है। वह षड्यंत्र के आधार पर प्रस्तुत की गई है। इसको कोई मान्यता नही है, वैधता नहीं है, तत्वहीन है, इसका कोई सार नहीं है। इसलिए इसका आधार गलत है। मै महोदव, यह जानना चाहता हूं कि. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): We may go into the merits of the case when we are going to discuss this Report. All these points have already been made. Why do you want to repeat them again?

श्री श्याम लाल यादव : इसलिए मै यह कहना चाहता हू कि क्या इस रिपोर्ट की प्रति हमको मिलेगी। अभी इस बारे मे पता लगाया गया तो मालूम पडा कि वह काउंटर मे अविलेबल नही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट की कापी हम लोगों को मिलेगी या नही मिलेगी ?

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH (Uttar Pradesh): Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Another lady Member has already taken your time.

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH: This is a politically-motivated Report. It is a well-established fact and it is known throughout India that this is a politically-motivated document. (*Interruptions*). As the Leader of the Opposition has said, instead of putting it on the Table of the House, it should have been put in the waste paper basket... (*Interruptions*).

SHRI PILOO MODY: And the excesses were also politically-motivated and, therefore, the punishments are also politically-motivated. What are you trying to say?

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: Sir, the declaration of emergency was ratified by both Houses of Parliament and, therefore, Sir, this appointment of the Shah Commission was not only politically motivated but it was unconstitutional. Mr. Justice Shah had no business and no power to enquire into the Act of Parliament. This is a direct insult to the Parliament of the country and this Report should be consigned to—as the leader of our party has said—the waste paper basket and should not be allowed to be discussed. This Report should be thrown into the waste paper basket and if my friend has got any objection, his remarks should also be consigned to the waste paper basket... (*Interruptions*)...

Another point is, it is an insult to the Parliament of the country that this Report has been screened by a committee of the bureaucrats and Secretaries and, therefore, this is an insult to the Parliamentary system of the Government. I would like to conclude with the remarks that this Report should not have been placed on the Table of the House; it should be consigned to the waste paper basket.

श्री सतपाल मित्तल (पजाब) : महोदय, भण्डारी जी की हम बहुत इज्जत करते है। उन्होंने यहां अपना व्याख्यान दिया है और दो तरह के विचार कहे है। मेरा कहना है कि वे खुद अपने अन्दर झांक कर देखे कि उनको ये बातें कहना शोभा देती है या नहीं including Mr. Piloo Mody who has raised the objection,

सारा हाउस जो है, कोई भी राज्य सभा का या पालियामेन्ट का मेम्बर वह पसन्द नही करेगा कि इस किस्म का एसपर्शन उस पर डाला जाय। उसका मतलब सारे हाउस का एसपर्शन है और मेरा ख्याल है कि भण्डारी जी ने ऐसा नहीं कहा होगा और हाउस के मेम्बरों के मुत्तलिक कहने का उनका मंतव्य नहीं होगा। इसलिए मै चाहता हूं कि भण्डारी साहब खुद खड़े होकर कहे कि उनका मकसद यह नही था कि किसी भी पालिया-मेन्ट के मेम्बर की जो इज्जत है वह किसी दूसरे नागरिक से कम है। यह अपने रिकार्ड में आप देख लीजिए। दूसरी बात यह कि जो भडारी साहब ने कहा कि इस हाऊस की सम्मति मे शाह कमीशन बनाया गया यह बात गलत ह। इस हाऊस ने कभी शाह* कमीशन.. It is a* यह स्लिप आफ टग है। यह बात उनको माननी चाहिए। वे जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और जनता पार्टी बार-बार दावा करती है कि हम सत्य पर चलते हैं, हम गांधी जी के प्रिंसिपल पर चलते हैं। वह दोनों बाते गलत है। इन दोनो बातो को मानना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को सदन में रख दिया है, या तो यह रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखी न जाए। अब जब रख दिया है तो वह सारी अखबारो में छपेगी। इसमे इस हाऊस के जो मेम्बर हैं उनका रिएक्शन साथ नहीं जाएगा, जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होगी। अगर इसको रख दिया है तो पालियामेंट को बढ़ाना चाहिए लेकिन मै यह चाहता हूं कि हमारे जो मेम्बर है वे अपना रिएक्शन इस रिपोर्ट पर दे लें तब इस डिस्कशन को कनकलूड करना चाहिए।

श्री कमलनाथ झा: उपसभाध्यक्ष महोदय, इंडीपेंडेट मेम्बर... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Jha, you have already spoken.

SHRI KAMALNATH JHA: I have not spoken on the Commission's reports.

श्रीमन्, मुझे शाह कमीशन के बारे मे कहना है। मेरे मित्र कुलकर्णी जी ने एक वाइटल प्वाइंट रेज किया। इस मुल्क में ज्युडिशरी की प्रतिष्ठा पर भी आघात पहुंचा है। मैं समझता हूं कि ज्यूडिशरी क्या होती है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट भी मानती है जब तक किसी एक्यूज्ड को बिलकुल फुलप्रूफ दोषी नहीं सिद्ध किया जाता तब तक उसको निर्दोष समझना जज का परम कर्त्तव्य है। जज खूनी को भी तब तक निर्दोष समझेगा जब तक प्रोसिक्युशन यह प्रूव न कर दे कि यह दोषी है। वह ज्यूडिशरी का एक सर्वमान्य तथ्य है। शाह कमीशन ने अपने गठन के जन्म से ही इस इटरनेशनली एक्सेपटेड प्रिंसिपल आफ ज्यूडिशरी की हत्या की है। शाह कमीशन की रिपोर्ट की प्रोसिडिंग मे लिखा है, पहले दिन से लिखा है। पहले दिन से शाह ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी दोषी है, इमरजेंसी में जुल्म हुए हैं संसार के किसी कमीशन ने, हिन्दुस्तान मे भी पचासों कमीशन बैठे हैं, ससार के कमीशनों के इतिहास मे ऐसा आज तक नही हुआ। शाह कमीशन के जस्टिस शाह जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इतने ऊंचे ओहदे को उन्होंने विभूषित किया है ज्यूडिशरी के फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ उन्होंने शुरू से आचरण किया है। इसलिए आज हम देखते है जब से शाह कमीशन की रिपोर्ट अखबारों मे छपने लगी है, लोग उस पन्ने को ही उलट देते हैं। ... (*Interruptions*) ... पीलू मोदी साहब शायद पढ़ते होंगे, उनको इंट्रेस्ट होगा लेकिन भारत की जनता में अगर सबसे बड़ा रिएक्शन हुआ है, जनता की सरकार के खिलाफ रिएक्शन हुआ है तो वह बिकाज आफ शाह कमीशन हुआ है। इसी के खिलाफ देश के लोगों ने निर्णय दिया है और इतनी जल्दी इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को रिहेबिलीटेट किया है। शाह कमीशन ने इंफ्रिजमेंट किया है ... (*Interruptions*) . भारत की जनता ...

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is enough. Please sit down. Let us hear Mr. Advani.

श्री कमलनाथ झा: इसलिए मैं कहता कहता हूं। भारत की जनता की सर्वोच्च कमेटी के सभा पटल पर इस रिपोर्ट को रख कर भारत की जनता का अपमान किया है, उसकी भावना को ठोकर मारी है। ऐसे कमीशन की रिपोर्ट को इस सभा पटल पर न रखा जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Now, let us hear the Leader of the House.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: What has the Government to say?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): He is getting up to say. You are not allowing him.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI LAL K. ADVANI): Members of the whole House have to say, both this side and that side. When I

*Expunged as ordered by the Chair.

sought the permission of the Chair, to intervene, it was only to point out that accusations and counter-accusations can be understood, but not the use of unparliamentary language. Therefore, my submission would be this. When I came in, I found that a Member was speaking and that the language he was using was unparliamentary obviously on the face of it. I would request you to go through the records and if there was use of unparliamentary language, that should be expunged.

Certain points have been raised just now. In fact, several points have been raised. This is not a debate, but because it has been occasioned by the laying of the Report of the Shah Commission—the interim Report—on the Table of the House, I would like to make it clear that the Commission's Report under the Commission of Inquiry Act is intended only to establish culpability. It is not a conviction; it is not a sentence. So the point that was raised by the hon. Member that the judiciary has to pronounce only after the process of prosecution is gone through is perfectly correct. In the Mundhra case, when Mundhra was found guilty, that did not land him into jail. It was only after a regular prosecution on the basis of which his conviction could be established. So this only establishes culpability and under the Commission of Inquiry Act, the Government has to come forth with a Memorandum of action taken also, and that has been done. Thank you.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I would like to bring to the notice of Mr. Advani—when he says about the Mundhra case—that no Commission appointed so far has declared and pronounced its judgment in the initial stage, as has already been pointed out.

SHRI LAL K. ADVANI: Let him wait for the judgment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Let us not go into those details here.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: No Commission has made such false propaganda at every stage of the enquiry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is a matter of opinion.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I only want...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Makwana, will you kindly sit down? Let us proceed with the business.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I only wanted to remind him...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You have already reminded him of that.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In the beginning itself Mr. Shah said that she was guilty. No Commission appointed so far has done that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: Let us proceed with the business. Will you kindly sit down? Order please.

SHRI SHRIKANT VERMA: I had raised certain constitutional points...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. The report of the Shah Commission, as per Rules, has already been laid on the Table of the House. So far as a discussion on it is concerned, it is for the Government to find business either in this Session or the next Session and, I am sure, all the hon. Members will have an opportunity to express their views on this. So far as the laying of the Report on the Table of the House is concerned, it has been in order; it has been done according to the Rules. The Commission was appointed under the Commission of Inquiry Act and it has been laid down there. Now let us proceed with the other business. Shri Kalyan Roy.

SHRI SITARAM KESRI (Bihar): What about those two points raised?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I have already said, they would be looked into. If there is any thing unparliamentary or derogatory, I can tell the hon. Members that it would be expunged.

(Several Hon. Members rose.)

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): If anybody wants to walk out, please walk out.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It is not a walk out. Order, order. Shri Kalyan Roy.

SHRI KALYAN ROY: Shah Commission has totally upset the mood. I am not in a mood.

श्रीमती सरोज खापर्डे . उपासभाध्यक्ष महोदय, शाह कमीशन की रिपोर्ट को आप सीधे वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Will the Lady Member kindly sit down and cooperate with the business of the House? It is not the Shah Commission, but it is the Coal Mines Bill. Shri Kalyan Roy.

THE COAL MINES NATIONALISATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 1978—contd.

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): The Shah Commission has upset all of us. The Commission should not have been set up at all.

I would not take up much time of the House. The last point I was dealing with was that you are starving the Coal India. The prices are going up and you should give a fair raise in the prices. I would only summarise my entire speech in 5 or 6 minutes. The second point I would like Mr. Ramachandran to note is that Rs. 92 crores has not been paid to Coal India so far by the public sector organisations. He says that Coal India will survive. How is it possible when Durgapur Steel, the Railways and the thermal power stations are not paying for the coal they are buying? Last session the hon'ble Member put the figure at Rs. 99 crores. Now he has reduced it to Rs. 92 crores. It is a shame that the public sector buys coal but they do not pay for it.

I am just summarising the points. Similarly, I would like to know about the fight going on between the Steel and the Coal Ministries. Only the other day the Minister stated that Coal India is able to supply all the needs of steel plants. The steel plants need 41,000 tonnes of coal per day. You also said that you are in a position to give them good coal as per quality control. But the ash content is not as much as Mr. Biju Patnaik wants to make out. On the other hand, the Steel Ministry is day after day propagating that the ash content is going up. Therefore, they have no alternative but to import coal which means an addition to coal cost. So this tussle between the two Ministries should be solved. The Coking Coal Ltd. is in a position to supply coal provided the price is paid whereas Mr. Biju Patnaik says that the Steel Ministry is going to buy coke oven coal. The entire washing plants are under Mr. Ramachandran. He should have looked into the functioning of the coking coal plants.

My third point is about distribution for which the Coal India cannot be blamed. The machinery should be controlled and distribution should be taken over from the hands of ex-miners and distribution should be made by the Coal India Ltd. itself. They should see to it that price of soft coke which is used by the ordi-